

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से
लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) से (35) XX XX XX

(36) "विक्रय कीमत" से इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर के सिवाय, किसी व्यवहारी को, व्यापार में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी भी किस्म के डिस्काउण्ट या रिबेट के रूप में अनुज्ञात किसी भी राशि को कम करते हुए, किन्तु किसी भी कानूनी उद्ग्रहण, या व्यवहारी के द्वारा माल या दी गयी सेवाओं के संबंध में उसके परिदान के समय या उसके पूर्व की गयी किसी भी बात के लिए प्रभारित किसी भी राशि को सम्मिलित करते हुए, किसी माल के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में संदत्त या संदेय रकम अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण I.- अवक्रय करार द्वारा किये गये किसी करार के मामले में, माल की उस तारीख को प्रचलित बाजार कीमत, जब ऐसा माल ऐसे करार के अधीन क्रेता को परिदत्त किया गया है, ऐसे माल की विक्रय कीमत समझी जायेगी;

स्पष्टीकरण II.- विक्रय के समय बीजक से यथाप्रकट नकद या व्यापार डिस्काउण्ट विक्रय कीमत में से अपवर्जित कर दिया जायेगा किन्तु भूतलक्षी प्रभाव से दिये गये कोई भी डिस्काउण्ट या प्रोत्साहन या रिबेट या पुरस्कार आदि अपवर्जित नहीं किये जायेंगे;

स्पष्टीकरण III.- जहां किसी संविदा के निबन्धनों के अनुसार, माल-भाड़े की लागत और माल के परिवहन के संबंध में के अन्य व्यय व्यवहारी के द्वारा क्रेता के लिए या उसकी ओर से उपगत किये जायें, वहां माल भाड़े की ऐसी लागत और अन्य व्यय विक्रय कीमत में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे, यदि बीजक में पृथक् रूप से प्रभारित किये गये हों;

(37) से (45) XX XX XX

XX XX XX XX

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से
लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

174. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) XX XX XX

(2) उप-धारा (1) या धारा 173 में उल्लिखित सीमा तक, उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा 173 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "ऐसा संशोधन" या, यथास्थिति, "संशोधित अधिनियम" कहा गया है),-

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय, कोई बात जो प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा; या

(ख) संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों और उनके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी किसी बात या आदेशों के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों या ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन आदेशों के अधीन किसी अधिकार, विशेषाधिकार या बाध्यता, अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा:

परन्तु किसी अधिसूचना के माध्यम से विनिधान के प्रति किसी प्रोत्साहन के रूप में मंजूर की गयी कोई कर छूट विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिवस को या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है; या

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज, जो शोध्य हैं या शोध्य हो सकते हैं, या किसी समपहरण या दण्ड को जो, संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के विरुद्ध किये गये किसी अपराध या अतिक्रमण के संबंध में उपगत या दिया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और लेखापरीक्षा को सम्मिलित करते हुए), निर्धारण कार्यवाहियां, न्यायनिर्णयन और कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां या बकाया की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माने, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार, और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और लेखापरीक्षा को

सम्मिलित करते हुए), निर्धारण कार्यवाहियों, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा या बकाया की वसूली या उपचार को संस्थित किया, जारी रखा, या प्रवृत्त किया, जा सकेगा, और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उद्गृहीत या अधिरोपित किया जा सकेगा मानो इन अधिनियमों को इस प्रकार संशोधित या निरसित नहीं किया गया हो; या

(च) कोई कार्यवाहियां, जो उक्त संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के अधीन नियत दिवस को, उससे पूर्व, या उसके पश्चात् संस्थित किसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश से संबंधित हैं, को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के अधीन जारी रखी जा सकेंगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियमों को संशोधित और निरसित नहीं किया गया हो।

(3) धारा 173 और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों के उल्लेख को निरसन के प्रभाव के संदर्भ में राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों के व्यापक रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जायेगा।

XX XX XX XX

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये

उद्धरण

XX XX XX XX

3. शुल्क से प्रभार्य लिखतें.- इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अन्तर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी है, अर्थात् :-

(क) XX XX XX

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित की गयी न होते हुए, इस तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की गयी है, और राज्य में स्थित किसी भी संपत्ति से

या राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी भी मामले या बात से संबंधित है, तथा राज्य में प्राप्त की गयी है:

परन्तु कोई भी शुल्क निम्नलिखित की बाबत प्रभार्य न होगा:-

- (i) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी लिखत पर, उन दशाओं में, जिनमें इस छूट के अभाव में, सरकार ऐसी लिखत की बाबत प्रभार्य शुल्क देने के लिए दायी होती;
- (ii) कोई लिखत जो पश्चात्पूर्वी अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के, अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित, अंश या सम्पत्ति के चाहे आत्यन्तिकतः या बंधक द्वारा या अन्यथा, विक्रय, अन्तरण या अन्य व्ययन के लिए है।

3-क. से 59.

XX

XX

XX

60. छपे प्ररूपों की दशा में छूट जिनकी निगमों को और आवश्यकता नहीं हो.-

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या उस दशा में कलक्टर जिसमें कि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, किसी बैंककार द्वारा या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों के छपे हुए प्ररूपों के लिए उपयोग में लाये गये स्टाम्पित कागजों के लिए समय परिसीमित किये बिना, छूट उस दशा में दे सकेगा, जिसमें कि किसी पर्याप्त कारण से ऐसे प्रारूप उपर्युक्त बैंककार कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा अपेक्षित न रह गये हों:

परन्तु यह तब जब कि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि ऐसे स्टाम्पित कागजों की बाबत शुल्क सम्यक् रूप से दे दिया गया है।

61. से 91.

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन		उचित स्टाम्प शुल्क	
1		2	
1. से 4.	XX	XX	XX
5. करार या करार का ज्ञापन-			
(क) से (ग)	XX	XX	XX

(घ) यदि वह किसी बैंक या वित्तीय कम्पनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित है;

उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत।

(ड) से (छ) XX XX

XX

5-क. XX XX

XX

6. ऐसे हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार या कोई भी अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि) अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित कोई भी दस्तावेजी सबूत :-

(1) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी भी संपत्ति पर विपण्य प्रतिभूति से भिन्न हक या साक्ष्य हो जाता हो; या

(2) जंगम संपत्ति का पण्यम् या गिरवी, जहां ऐसा निक्षेप, गिरवी, उधार में अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गयी है,-

(क) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर, जो करार या हक विलेखों के निक्षेप के सबूत को साक्ष्यित करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है:

उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत।

(ख) यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं है।

प्रतिभूत रकम के लिए खण्ड (क) के अधीन संदेय शुल्क का आधा।

छूट: कृषि उपज के पण्यम् या गिरवी की कोई लिखत यदि वह अनुप्रमाणित हो।

7. से 20-क.

XX

XX

XX

21 धारा 2 (xi) द्वारा यथा-परिभाषित

हस्तान्तरण-पत्र.-

(i) से (ii)	XX	XX	XX
(iii) यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो,-			अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपये के अध्यक्षीन रहते हुए- (i) ऐसे समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आबंटित या रद्द किये गये शेयर के बाजार मूल्य या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, में समाविष्ट कुल रकम और संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, या (ii) अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, जो भी अधिक हो।
(iv)	XX	XX	XX
22. से 57.	XX	XX	XX
58. संकर्म संविदा अर्थात् उसके निष्पादन में माल में की संपत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) अन्तरण को अन्तर्वर्तित करने वाले संकर्म और मजदूरी या सेवाओं की कोई संविदा और उसमें उप-संविदा भी सम्मिलित है।			अधिकतम पन्द्रह हजार रूपये के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी संविदा में रखी गयी रकम या मूल्य का 0.25 प्रतिशत।
XX	XX	XX	XX
राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) से लिये गये उद्धरण			
XX	XX	XX	XX

4. कर का अधिरोपण.- (1) इस अधिनियम द्वारा या तदधीन बनाये गये नियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर राज्य में उपयोग में लिये जाने वाले या उपयोग के लिए रखे जाने वाले समस्त मोटर यानों पर,-

(क) ऐसे यानों के संबंध में जो खण्ड (ख), (ग), (गग) या (घ) के अन्तर्गत नहीं आते हों, कर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाये, जो चैसिस/यान की लागत के 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी:

परन्तु जहां दरें राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या मासिक आधार पर विनिर्दिष्ट नहीं की जायें और यदि कर का त्रैमासिक रूप से, अर्द्धवार्षिक रूप से या मासिक रूप से संदत्त किया जाना अनुज्ञेय हो तो संदेय रकम कर की वार्षिक दर की क्रमशः एक चौथाई, आधी या एक बटे बारह की समतुल्य रकम होगी;

(ख) परिवहनेतर यानों के मामले में एकबारीय कर, जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाये, जो यान/चैसिस की लागत के 16% से अधिक नहीं होगा:

परन्तु एकबारीय कर के साथ-साथ, ऐसे किसी मोटर यान का, जिस पर एकबारीय कर संदेय है, कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा ऐसे कोई भी कर या शास्ति, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 5 के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो ऐसे यानों पर समय-समय पर लागू थीं:

परन्तु यह और कि ऊपर उल्लिखित मोटर यान के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जायें, अतिरिक्त एकबारीय कर संदेय होगा;

(ग) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत और राजस्थान में सड़कों का उपयोग करने वाले मोटर यानों के संबंध में, कर, ऐसी दरों से, जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचित की जायें, जो यात्री यानों की दशा में 7 दिन या उसके भाग के लिए 500/- रुपये प्रति सीट से अधिक नहीं होगा और माल यानों की दशा में 30 दिन या उसके भाग के लिए, जी.वी. डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग के

लिए 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा और संनिर्माण उपस्कर यानों की दशा में लदान रहित वजन के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए, 30 दिन या उसके भाग के लिए 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा;

(गग) से (घ) XX XX XX

(ड) परिवहन यानों की दशा में एकबारीय कर ऐसी दरों से, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जायें, जो यान/चैसिस की लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु एकबारीय कर के अतिरिक्त ऐसे परिवहन यान, जिस पर एकबारीय कर संदेय है, के स्वामी या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई भी कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) के अध्याय 5 के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो ऐसे यानों पर समय-समय पर लागू थी:

परन्तु यह और कि परिवहन यानों का स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को या तो खण्ड (क) के अधीन उद्गृहीत कर या खण्ड (ड) के अधीन उद्गृहीत एकबारीय कर संदत्त करने का विकल्प होगा,

उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन एकबारीय कर या एकमुश्त कर के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों से भिन्न मोटर यानों पर कर, मोटर यान के स्वामी द्वारा उस कालावधि को छोड़कर संदेय होगा, जिसके दौरान वह स्वामी कराधान अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र विहित रीति से अभ्यर्पित कर देता है कि यान ऐसे कारणों से जो विहित किये जायें, उपयोग में नहीं आया है; या कराधान अधिकारी का यह समाधान कर देता है कि यान का निम्नलिखित कारणों से उपयोग नहीं किया गया है:-

- (i) कि सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा मोटर यान को चलने से अवरूद्ध किया गया था;
- (ii) कि मोटर यान किसी दुर्घटना में अन्तर्गस्त था और पुलिस को इस आशय की रिपोर्ट की गई थी और दुर्घटना के कारण उसको उपयोग में नहीं लाया गया था;

(iii) कि मोटर यान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अधीन कर को वसूली के लिए कुर्क किया गया था या सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा जारी किये गये कुर्की के वारण्ट के अधीन कुर्क किया गया था और कुर्की की कालावधि के दौरान वह यान उसके कब्जे में नहीं रहा था:

परन्तु ऐसे अभ्यर्पण या उपयोग में न लाने की कालावधि मंजिली गाड़ियों के लिए सात दिन से कम और मंजिली गाड़ियों से भिन्न के लिए एक मास से कम की नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे यान, जिसके लिए धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ड) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर का संदाय कर दिया है, से भिन्न कोई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के पश्चात् भी चलता हुआ पाया जाये वहां ऐसे यान पर कर उस सम्पूर्ण कालावधि के लिए जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण अभ्यर्पित किया गया था, कर की रकम के पांच गुने के बराबर शास्ति सहित तुरन्त संदेय होगा, किन्तु ऐसा कोई भी कर या शास्ति मरम्मत के लिए या परीक्षण प्रयोजनों के लिए जा रहे खाली यानों से प्रभारित नहीं किया जायेगा।

4-ख. विशेष सड़क कर.- धारा 4 के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, ऐसे परिवहन यानों, जिनके लिए धारा 4-ग के अधीन संदेय कर एकमुश्त संदत्त कर दिया गया है, के सिवाय, समस्त परिवहन यानों पर एक विशेष सड़क कर ऐसी दरों से उद्गृहीत किया जायेगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, जो यात्री यानों के संबंध में 2000/-रु. प्रति दिन से अधिक नहीं होगा और अन्य राज्यों के माल यानों के संबंध में या इस राज्य के अस्थायी परमिटों पर चलने वाले यानों के लिए जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू. के प्रत्येक एक हजार कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए तीस दिन के लिए प्रति एक हजार कि.ग्रा. वहन क्षमता पर 250/- रु. से अधिक नहीं होगा और अन्य यानों के संबंध में चेसिस/यान की लागत के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.- कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए चेसिस/यान की लागत में क्रय कीमत और ऐसे अन्य तत्व सम्मिलित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे मोटर यानों से, जिनके लिए धारा 4-ग के अधीन एकबारीय कर संदत्त कर दिया गया है, भिन्न कोई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के पश्चात् भी चलता हुआ पाया जाये वहां ऐसे यान पर विशेष सड़क कर, सम्पूर्ण कालावधि के लिए जिसके लिए ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभ्यर्पित किया गया था, विशेष सड़क कर की रकम के पांच गुना के बराबर शास्ति सहित तुरंत संदेय होगा परन्तु ऐसा कोई भी कर या शास्ति, मरम्मत के लिए या परीक्षण प्रयोजनों के लिए जा रहे खाली यानों से प्रभारित नहीं की जायेगी।

4-ग. एकमुश्त कर का अधिरोपण.- धारा 4 और धारा 4-ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसे नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें, समस्त परिवहन यानों पर कर ऐसी दरों से एकमुश्त उद्गृहीत किया जायेगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, जो यान/चैसिस की लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु परिवहन यान का स्वामी या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के पास या तो धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ड) और धारा 4-ख के अधीन उद्गृहीत कर संदत्त करने या धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर संदत्त करने का विकल्प होगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा 01-4-2007 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किये गये परिवहन यानों के ऐसे वर्ग, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के स्वामियों या कब्जा रखने वाले व्यक्तियों से, धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ड) और धारा 4-ख के अधीन संदेय कर के स्थान पर धारा 4-ग के अधीन कर के एकमुश्त संदाय की अपेक्षा कर सकेगी।

4-घ. ग्रीन कर का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय पर, इस सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायें, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

सारणी

XX

XX

XX

XX

(2) XX XX XX

4-ड. अधिभार का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उक्त धाराओं के अधीन अधिरोपित कर में, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 15) के प्रारंभ से, उक्त कर के 20 प्रतिशत से अनधिक, ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, अधिभार द्वारा वृद्धि की जायेगी।

(2) XX XX XX

5. कर का संदाय.- (1) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर और उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन, धारा 4, धारा 4-ख और धारा 4-ग के अधीन उद्ग्रहणीय कर, मोटर यान के प्रत्येक स्वामी द्वारा या उस पर कब्जा अथवा नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से, अग्रिम रूप से संदत्त किया जायेगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर देने के दायी विशेष वर्गों के यानों या व्यक्तियों के मामले में कर के संदाय की सीमा को भविष्य या भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ा सकेगी:

परन्तु यह और कि धारा 4-ग के अधीन संदेय एकमुश्त कर एक बार में या एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर तीन समान किस्तों में ऐसी रीति से संदत्त किया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(2) जहां किसी भी मोटर यान पर, संदेय एकबारीय कर या एकमुश्त कर से अन्यथा कर, किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम बार संदेय होता है वहां संदेय कर, यदि वार्षिक दर विहित हो, प्रत्येक कलैण्डर मास या उसके किसी भाग के लिए वार्षिक दर का बारहवां भाग होगा:

परन्तु जहां धारा 4ख के अधीन अनन्य रूप से नगर मार्गों पर चलने वाली उन मंजिली गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों पर कर, किसी भी मास के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार संदेय हो जाता है वहां संदेय कर आनुपातिक आधार पर उस मास की शेष कालावधि के लिए होगा:

परन्तु यह और कि जहां संविदा यान पर धारा 4ख के अधीन कर, प्रथम बार किसी भी मास के प्रारंभ के पश्चात् संदेय होता है, वहां संदेय कर आनुपातिक आधार पर उस मास की शेष कालावधि के लिए होगा।

(3) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ड) या धारा 4-ग के अधीन संदेय पूरा कर या कर की प्रथम किस्त,-

(क) जहां मोटर यान, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 5 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने पर या उसके पश्चात् क्रीत किया जाता है या राज्य में उपयोग में लेने के लिए लाया या उपयोग के लिए रखा जाता है, वहां ऐसे क्रय या ऐसे लाये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर या राज्य में ऐसे यान के रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन की तारीख को, जो भी पहले हो; या

(ख) जहां मोटर यान राजस्थान वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 5 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने के पूर्व राज्य में उपयोग में लाया गया है या रखा गया है, वहां ऐसे प्रवृत्त होने के साठ दिन के भीतर-भीतर,

संदेय होगा।

(4) जहां कोई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के पश्चात् भी चलता हुआ पाया जाये, वहां ऐसे यान पर धारा 4 और धारा 4-ख के अधीन उद्गृहीत कर, स्वामी या मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस सम्पूर्ण कालावधि के लिए, जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र अभ्यर्पित किया गया था, कर की रकम की पाँच गुना के बराबर शास्ति सहित तुरन्त संदेय होगा किन्तु ऐसा कोई भी कर या शास्ति मरम्मत के लिए या परीक्षण प्रयोजनों के लिए जा रहे खाली यानों पर प्रभारित नहीं की जायेगी।

XX

XX

XX

XX

7. कर का प्रतिदाय.- (1) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने कर धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ड) के अधीन या धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर से अन्यथा या कर की किस्त संदत्त कर दी है, कराधान अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में ऐसा कर या उसकी किस्त का संदाय कर दिया गया है, पिछली बार कर या उसकी किस्त का संदाय किये जाने के समय से कम से कम लगातार एक मास से अन्यून की कालावधि तक उपयोग में नहीं लिया गया है तो वह उस कालावधि के, जिसके लिए ऐसे कर या किस्त का संदाय कर दिया गया है, प्रत्येक पूरे मास के लिए, ऐसे यान के संबंध में संदत्त कर की वार्षिक दर के 1/12 के बराबर रकम के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(2) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ड) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर का संदाय कर दिया है, कराधान अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में कर का संदाय कर दिया गया है, राज्य के बाहर ले जाया गया है या

पूरी तरह से विनष्ट हो गया है या ऐसे यान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जो कम कर का दायी है तो वह विहित रीति से अनुपाततः ऐसे कर के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(3) कराधान अधिकारी, देय कर से अधिक संदत किसी भी रकम का विहित रीति से प्रतिदाय या समायोजन कर सकेगा।

XX

XX

XX

XX

10. रसीद और टोकन या कर प्रमाण-पत्र का दिया जाना.- (1) कराधान अधिकारी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने उसे कर संदत किया है,-

(क) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले किसी भी मोटर यान के सम्बन्ध में, संदत कर की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने वाली एक रसीद और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाला, जो कि विहित की जायें, एक कर प्रमाण-पत्र भी; या

(ख) ऊपर खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले से भिन्न मोटर यान के सम्बन्ध में, एक यथापूर्वोक्त रसीद और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाला, जो कि विहित की जायें, एक टोकन देगा और परिदत्त करेगा:

परन्तु किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में कोई भी टोकन जारी नहीं किया जायेगा यदि धारा 4-ख के अधीन संदेय विशेष सड़क-कर और राजस्थान यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 18), जैसा कि वह राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) अधिनियम, 1982 के पूर्व विद्यमान था, के अधीन बकाया देय और सृष्ट और-मांग, यदि कोई हो, संदत न कर दी गयी हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन किसी भी मोटर यान का राजस्थान में उपयोग तब तक नहीं किया जायेगा या उसे उपयोग के लिए तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक उसके स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने,-

(क) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ड) के अधीन आने वाले किसी यान के मामले में, कोई कर प्रमाण-पत्र, जो सदैव ऐसे यान में रखा जायेगा, या

(ख) ऊपर खण्ड (क) के अधीन आने वालों से भिन्न यान के मामले में, एक विधिमान्य टोकन, जो सदैव ऐसे यान पर विहित रीति से प्रदर्शित किया जायेगा,

अभिप्राप्त न कर लिया हो।

10-क. विशेष टोकन का दिया जाना.- किसी मोटर यान का कोई भी स्वामी, जिसने मोटर यान कर और विशेष सड़क कर का संदाय अग्रिम रूप से कर दिया है, विहित फीस के संदाय पर विशेष टोकन देने के लिए कराधान अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और कराधान अधिकारी विशेष टोकन ऐसी रीति से जारी करेगा, जो विहित की जाये।

10-ख. कम्प्यूटरकरण.- इस अधिनियम के अधीन रसीद, कर प्रमाण पत्र, टोकन, विशेष टोकन आदि देने के कार्य का ऐसी रीति से कम्प्यूटरकरण किया जा सकेगा, जो विहित की जाये। ऐसा कार्य किसी भी एजेन्सी को सौंपा जा सकेगा और उपगत खर्चा यान के स्वामी से ऐसी रीति से वसूल किया जा सकेगा, जो विहित की जाये।

11. अपराध.- (1) जो कोई,-

(क) रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में या अन्यथा, राज्य में उपयोग में लिये गये या उपयोग के लिए रखे गये किसी भी मोटर यान को, उक्त यान के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय कर या अतिरिक्त कर या विशेष सड़क कर की रकम संदत्त किये बिना अपने कब्जे या नियंत्रण में रखता है; या

(ख) ऐसी घोषणा या अतिरिक्त घोषणा परिदत्त करता है जिसमें इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसमें उपवर्णित की जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का पूर्णतः और सही कथन नहीं किया गया है; अथवा

(ग) किसी भी अधिकारी को धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में बाधित करता है या जब धारा 17 के अधीन उक्त अधिकारी द्वारा मोटर यान को रोकने की अपेक्षा किये जाने पर उसे नहीं रोकता है;

वह दोषसिद्धि पर इतने जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उक्त यान के सम्बन्ध में संदेय वार्षिक कर के दुगुने से कम नहीं होगा किन्तु जो ऐसे वार्षिक कर के पांच गुने तक का हो सकेगा।

(2) XX XX XX
XX XX XX XX

22. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) XX XX

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त प्रयोजनों या उनमें से किन्हीं के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्:-

(क) से (कक) XX XX XX

(ख) किसी भी प्रमाण-पत्र, घोषणा, विवरणी, नोटिस, रसीद या टोकन का प्ररूप और उसमें कथित की जाने वाली विशिष्टियां, और मोटर यान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना;

(खख) XX XX XX

(खखख) वह रीति विहित करना जिससे इस अधिनियम के अधीन रसीद, प्रमाण-पत्र, टोकन, विशेष टोकन आदि देने के कार्य का कम्प्यूटरकरण किया जाये और किसी भी एजेन्सी को सौंपा जाये और उपगत खर्चा उस यान के स्वामी से वसूल किया जाये;

(ग) से (झ) XX XX XX

XX XX XX XX

(Authorised English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2019-20 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2019.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3, 8 and 9 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

**CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In clause (36) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), after the existing Explanation III, the following Explanation IV shall be added, namely:-

“Explanation IV.- The amount received or receivable by oil companies for the sale of diesel and petrol to the retail outlets in the State shall be deemed to be equivalent to the price on which the retail outlets sell these commodities to the consumer;”.

**CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX
ACT, 2017**

4. Amendment of section 174, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new sub-section (2A) shall be inserted, namely:-

“(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions as appears to it necessary or expedient, for-

- (i) making omissions from, additions to and adaptations and modifications of the rules made, notifications and orders issued under the repealed Acts, from such date as may be specified therein;
- (ii) recovery, exemption, waiver, write off or rebate of tax leviable under the repealed Acts including framing of any scheme for settlement of outstanding dues recoverable under the repealed Acts; and
- (iii) specifying the authority, officer or person who shall be competent to exercise such functions exercisable under any of the repealed Acts or any rules made, notifications or orders issued thereunder as may be mentioned in the said notification.”.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

5. Insertion of section 8A, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- After the existing section 8 and before the existing section 9 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the following new section 8A shall be inserted, namely:-

“8A. Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases.- Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in the Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty payable under this Act, by any class of suppliers or persons, subject to such terms and conditions as may be specified therein.”.

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

6. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 3 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

- "(b) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State on or after the said date, relates to any matter or thing done or to be

done in the State and is received in the State, or relates to any property situate in the State:".

7. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 60 of the principal Act, for the existing expression "The Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority in this behalf", the expression "The Collector" shall be substituted.

8. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

- (i) in clause (d) of Article 5, for the existing expression "0.15%" appearing under column No. 2, the expression "0.25%" shall be substituted;
- (ii) in clause (a) of Article 6, for the existing expression "0.15%" appearing under column No. 2, the expression "0.25%" shall be substituted;
- (iii) in clause (iii) of Article 21, the existing expression "Subject to a maximum of twenty five crores rupees-" appearing under column No. 2, shall be deleted; and
- (iv) in Article 58, the existing expression "subject to maximum of rupees 15,000/-" appearing under column No. 2 shall be deleted.

CHAPTER VI AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

9. Amendment of section 4, Rajasthan Act No.11 of 1951.- In section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-
 - (I) for the existing clauses (a) and (b), the following shall be substituted, namely:-
 - "(a) a tax in respect of such vehicles which are not covered by clause (b), (c), (cc) and (d) at such rates as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette which shall not exceed Rs. 2000/- per thousand Kg. of Gross Vehicle Weight or part thereof per year for goods vehicles and Rs. 2000/- per seat per month for passenger vehicles of this State:

Provided that where the rates are not specified, on quarterly, half yearly or monthly basis, by the State Government, by notification in the Official Gazette and if the tax is permissible to be paid quarterly, half yearly or monthly, the amount payable shall be equivalent to the one fourth, one half or one twelfth respectively of the annual rate of tax;

- (b) a one time tax in the case of non transport vehicles and in case of such class of transport vehicles, as may be specified by notification in the Official Gazette, at such rates as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette which shall not exceed 50% of the cost of the vehicle/chassis:

Provided that on every transfer of ownership of non transport vehicles mentioned above, an additional one time tax shall be payable at such rates as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette;"

- (II) in clause (c), for the existing expression "not exceed Rs. 500/- per seat for 7 days or part thereof in case of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 250/- per thousand Kg. Gross Vehicle Weight/Registered Laden Weight", the expression "not exceed Rs. 2000/- per day in case of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 2000/- per thousand Kg. Gross Vehicle Weight" shall be substituted;

(III) the existing clause (e) shall be deleted; and

(ii) in sub-section (2),-

(I) the existing expression "or lump sum tax" shall be deleted; and

(II) in second proviso, for the existing expression "or clause (e) of sub-section (1) of section 4 or lump sum tax under section 4-C", the expression "of sub-section (1) of section 4" shall be substituted.

10. Deletion of section 4-B and 4-C, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- The existing sections 4-B and 4-C of the principal Act, shall be deleted.

11. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (1) of section 4-D of the principal Act, for the existing expression "sections 4, 4-B and 4-C", the expression "section 4" shall be substituted.

12. Amendment of section 4-E, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (1) of section 4-E of the principal Act, for the existing expression "sections 4, 4-B and 4-C", the expression "section 4" shall be substituted.

13. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 5 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-

- (I) for the existing expression "section 4, section 4-B and section 4-C", the expression "section 4" shall be substituted;
- (II) in the first proviso, for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted, and the existing second proviso shall be deleted;
- (ii) in sub-section (2),-
 - (I) the existing expression "or lump sum tax" shall be deleted;
 - (II) in the first proviso, for the existing expression "section 4-B", the expression "clause (a) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;
 - (III) in the second proviso, for the existing expression "section 4-B", the expression "clause (a) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;
- (iii) in sub-section (3), for the existing expression "clause (b) or (e) of sub-section (1) of section 4 or full tax or first instalment of tax under section 4-C", the expression "clause (b) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted; and
- (iv) in sub-section (4), for the existing expression "section 4 and section 4-B", the expression "section 4" shall be substituted.

14. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing section 7 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"7. Refund of tax.- (1) When any person who has paid the tax other than one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 proves to the satisfaction of the Taxation Officer that the motor vehicle in respect of which such tax has been paid, has not been used for a continuous period of not less than one month since the tax was last paid, he shall be entitled to the refund of an amount equal to 1/12th of the annual rate of the tax paid in respect of such vehicle for each complete month of the period for which such tax has been paid.

(2) When any person who has paid one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 proves to the satisfaction of the Taxation Officer that the motor vehicle, in respect of which such tax has been paid, has been taken out of the State or has completely been destroyed shall be entitled to the refund of such tax on pro rata basis in the prescribed manner.

(3) The Taxation Officer may refund or adjust in the prescribed manner any amount paid in excess of the tax due."

15. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 10 of the principal Act,-

- (i) in clause (b) of sub-section (1), for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted, and the existing proviso shall be deleted;
- (ii) in clause (a) of sub-section (2), for the existing expression "clause (b) and clause (e)", the expression "clause (b)" shall be substituted; and
- (iii) in clause (b) of sub-section (2), for the existing expression "exhibited on", the expression "kept in" shall be substituted.

16. Deletion of section 10-A, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- The existing section 10-A of the principal Act shall be deleted.

17. Amendment of section 10-B, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 10-B of the principal Act, the existing expression ", special token" shall be deleted.

18. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In clause (a) of sub-section (1) of section 11 of the principal Act, the existing expression "or special road tax" shall be deleted.

19. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (2) of section 22 of the principal Act,-

- (i) in clause (b), for the existing expression "exhibiting a token on", the expression "keeping a token in" shall be substituted; and
- (ii) in clause (bbb), the existing expression "special token" shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Presently, the levy of tax on petrol and diesel is at the first point in the series of sales by a registered dealer. Thus, the oil companies are paying tax on the price charged to the retail outlets and not on the price paid by the consumers. In order to collect tax on the price which the consumer pays to the retail outlets, it is proposed to add a new, explanation IV in clause (36) of section 2 of Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

On introduction of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, certain existing Acts were repealed. At present, there is no enabling provision in the said Act to dispose of certain issues, related to the repealed Acts. Therefore, to dispose of these issues it is considered appropriate to amend section 174 of the aforesaid Act.

THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

Presently, the State Government has power to grant exemption from payment of Electricity Duty. However, there is no provision for waiver or reduction of penalty and interest payable by such class of suppliers or persons in the Act. Keeping this objective in view, it is proposed to insert a new section 8A in the Act to empower the State Government to reduce or waive the penalty and interest payable by such class of suppliers or persons.

RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Section 3 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 makes the instruments chargeable with stamp duty which is mentioned in the Schedule whether such instrument is executed in State or out of the State. Instrument executed out of the State becomes chargeable only if such instrument relates to any property situate, or to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State.

These provisions are being misused to avoid stamp duty. Instruments relating to immovable property situate in the State of Rajasthan are being intentionally executed out of the State.

Therefore with a view to make the provisions more clear and to plug the revenue evasion, clause (b) of section 3 is proposed to be amended suitably to charge the instruments, with stamp duty, related to any property situate in the State of Rajasthan whether such instrument received in State of Rajasthan or not.

As per present provisions of section 60 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 allowance for stamp papers used for printed form of instruments by any banker or by any other incorporated company or other body corporate can be made by the Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority. For other categories of stamp papers the Collector is empowered to make the allowance. With a view to simplify the procedure the Collector is proposed to be empowered to make allowance for such category of stamp papers also.

Clause (d) of Article 5 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the rate of stamp duty on an agreement or a memorandum of an agreement relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or finance company from 0.15 percent to 0.25 percent.

Clause (a) of Article 6 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the rate of stamp duty on an agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds, pawn or pledge from 0.15 percent to 0.25 percent.

Clause (iii) of Article 21 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to delete the provision regarding maximum limit of stamp duty on conveyance relating to the order under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of a company.

Article 58 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to delete the provision regarding maximum limit of stamp duty payable on works contract.

THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

Section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 empowers the State Government to levy taxes on motor vehicles kept or kept for use in the State. Section 4-B provides imposition of special road tax on all transport vehicles on the basis of cost of the chassis or vehicle in the cases of goods vehicles and passenger vehicles. In most of the categories of contract carriage and stage

carriage a ceiling had been fixed owing to exponential increase of cost of vehicles and induction of very high cost vehicles in the market. This has led to disproportionate amount of payable taxes by a vehicle. Therefore, it seems reasonable and appropriate to impose motor vehicle tax on the basis of Gross Vehicle Weight for goods vehicle and seating capacity for passenger vehicles. Therefore, section 4 is proposed to be amended.

There is multiplicity of taxation on motor vehicles in the state. Transport vehicles require to pay motor vehicle tax under section 4 and special road tax under section 4-B of the Act. In order to make simplification of tax pattern, payment procedure and digitisation of tax records, a single motor vehicles tax under clause (a) of sub-section (1) of section 4 is proposed to be levied on all transport vehicles. Accordingly section 4-B of the Act is proposed to be deleted.

Non transport vehicles require to pay one time tax at the time of registration under clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Act. Likewise certain transport vehicles as goods vehicle having Gross Vehicle Weight up to 16500 Kg., three wheeled passenger vehicles, cabs, maxi cabs and contract carriage buses/private service vehicles up to seating capacity of 22, are required to pay lump sum tax under section 4-C of the Act. Both the taxes are of similar nature and paid for life time of a vehicle. Therefore, these taxes are proposed to be put under single category i.e. one time tax. Accordingly, section 4-C of the Act and the expression 'lump sum tax' wherever occurring in the Act is proposed to be deleted.

A refund of paid one time tax is provisioned owing to conversion of category of vehicle from non transport to transport. Since both the categories are proposed to be put under payment of one time tax, only difference amount of tax would be realised in the event of conversion of category. Therefore, refund of one time tax will not be required, accordingly section 7 is proposed to be amended.

Certain consequential amendments are also proposed to be made in sections 4, 4-D, 4-E, 5, 10, 10-A, 10-B, 11 and 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

(अशोक गहलोट)

Minister Incharge.

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल
महोदय की सिफारिश**

[सं.प.12(43)वित्त/कर/2019 दिनांक 10.07.2019

प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX
ACT, 2003
(Act No. 4 of 2003)**

XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(1) to (35) XX XX XX

(36) “sale price” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I.- In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II.- Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III.- Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

(37) to (45) XX XX XX

XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS AND
SERVICES TAX ACT, 2017
(Act No. 9 of 2017)**

XX XX XX XX

174. Repeal and saving.- (1) XX XX XX

(2) The repeal of the said Acts and the amendment of the Acts specified in section 173 (hereafter referred to as “such amendment” or “amended Act”, as the case may be) to the extent mentioned in sub-section (1) or section 173 shall not-

- (a) revive anything not in force or existing at the time of such amendment or repeal; or
- (b) affect the previous operation of the amended Acts or repealed Acts and orders or anything duly done or suffered thereunder; or
- (c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the amended Acts or repealed Acts or orders under such repealed or amended Acts:

Provided that any tax exemption granted as an incentive against investment through a notification shall not continue as privilege if the said notification is rescinded on or after the appointed day; or

- (d) affect any tax, surcharge, penalty, interest as are due or may become due or any forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed against the provisions of the amended Acts or repealed Acts; or
- (e) affect any investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and any other legal proceedings or recovery of arrears or remedy in respect of any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment, as aforesaid, and any such investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and other legal proceedings or recovery of arrears or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, forfeiture or punishment may be levied or imposed as if these Acts had not been so amended or repealed; or
- (f) affect any proceedings including that relating to an appeal, revision, review or reference, instituted before, on or after the appointed day under the said amended Acts or repealed Acts and such proceedings shall be continued under the said amended Acts or repealed Acts as if this Act had not come into force and the said Acts had not been amended or repealed.

(3) The mention of the particular matters referred to in section 173 and sub-section (1) shall not be held to prejudice or affect the general application of provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) with regard to the effect of repeal.

XX

XX

XX

XX

THE SCHEDULE
(See section 3)

Description of instrument		Proper Stamp Duty
1		2
1. to 4.	XX XX	XX
5. Agreement or memorandum of an agreement-		
(a) to (c)	XX XX	XX
(d) if relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or Finance Company;		0.15% of the amount of loan or debt.
(e) to (g)	XX XX	XX
5-A	XX XX	XX
<p>6. Agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds, pawn or pledge i.e. any documentary proof relating to:-</p> <p>(1) the deposit of title-deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever, other than a marketable security, or</p> <p>(2) the pawn or pledge of movable property, where such deposit, pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt ,-</p>		
(a) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement or proof of deposit of title deeds.		0.15 percent of the amount of loan of debt.
(b) if such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument.		Half the duty payable under clause (a) for the amount secured.
Exemption: Instruments of pawn or pledge of agricultural produce, if unattested.		
7. to 20-A.	XX XX	XX
21. Conveyance as defined by section 2 (xi),-		
(i) to (ii)	XX XX	XX
(iii) if relating to the order under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) or section 44-A		Subject to a maximum of twenty five crores rupees-

<p>of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of a company.</p>	<p>(i) an amount equal to four percent of the aggregate amount comprising of the market value of share issued or allotted or cancelled in exchange of or otherwise, or on the face value of such shares, whichever is higher and the amount of consideration, if any, paid for such amalgamation, demerger or reconstruction, or (ii) an amount equal to four percent of the market value of the immovable property situated in the State of Rajasthan of the transferor company, whichever is higher.</p>
(iv) XX XX	XX
22. to 57. XX XX	XX
58. Works contract that is to say a contract for works and labour or services involving transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) in its execution and includes a sub-contract.	0.25 percent of the amount or value set forth in such contract subject to maximum of rupees 15,000/-.
XX XX	XX XX

THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

[Act No. XI of 1951]

XX

XX

XX

XX

4. Imposition of tax.- (1) Save as otherwise provided by this Act or by the Rules made thereunder or any other law for the time being in force, there shall be levied and collected on all motor vehicles used or kept for use in the State,-

- (a) a tax in respect of such vehicles which are not covered by clause (b), (c), (cc) or (d), at such rates as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette which shall not exceed 10% of the cost of the chassis/vehicle per annum:

Provided that where the rates are not specified, on quarterly, half yearly or monthly basis, by the State Government, by notification in the Official Gazette and if the tax is permissible to be paid quarterly, half yearly or monthly, the amount payable shall be equivalent to the one fourth, one half or one twelfth respectively of the annual rate of tax;

- (b) a one time tax in the case of non transport vehicles at such rates as may be notified by the State Government by notification in the Official Gazette which shall not exceed 16% of the cost of the vehicle/chassis:

Provided that in addition to one Time Tax there shall be paid by the owner or person having possession or control of a motor vehicle on which one time tax is payable, any tax or penalty as was payable under this Act for any period prior to the coming into force of the provisions of Chapter V of the Rajasthan Finance Act, 2005 (Act No. 15 of 2005) at such rates as were applicable to such vehicles from time to time:

Provided further that on every transfer of ownership of motor vehicle mentioned above, an additional one time tax shall be payable at such rates as may be notified by the State Government in the Official Gazette;

- (c) a tax in respect of motor vehicles registered outside the State and using roads in Rajasthan, at such rates, as may be notified by the State Government in the Official Gazette which shall not exceed Rs. 500/- per seat for 7 days or part thereof in case of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 250/- per thousand Kg. Gross Vehicle Weight/Registered Laden Weight or part thereof for 30 days or part

thereof in case of goods vehicles and shall not exceed Rs. 5000/- per thousand Kg. of Unladen Weight or part thereof for 30 days or part thereof in case of Construction Equipment Vehicles;

(cc) to (d) XX XX XX

- (e) a one time tax in respect of transport vehicles at such rates as may be notified by the State Government in the Official Gazette, which shall not exceed 50% of the cost of the vehicle/chassis:

Provided that in addition to one time tax, there shall be paid by the owner or person having possession or control of transport vehicle on which one time tax is payable any tax or penalty as was payable under this Act for any period prior to the coming into force of the provisions of the Chapter V of the Rajasthan Finance Act, 2005 (Act No. 15 of 2005) at such rates as were applicable to such vehicles from time to time:

Provided further that the owner or person having possession or control of transport vehicles shall have option either to pay tax levied under clause (a) or one time tax levied under clause (e).

(2) A tax on motor vehicles other than those covered by one time tax or lump sum tax shall be payable under this section by the owner of motor vehicle except for the period during which the owner surrenders the certificate of registration to the taxation officer, in the prescribed manner, that the vehicle has remained out of use for such reasons as may be prescribed, or satisfies the taxation officer that vehicle has not been used due to following reasons:-

- (i) that the motor vehicle was restrained from plying by the competent court or authority;
- (ii) that the motor vehicle was involved in an accident and a report to this effect was made to the police and because of accident it remained out of use;
- (iii) that the motor vehicle was attached for the recovery of tax under the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) by the competent authority or attached under the warrant of attachment issued by the competent authority or court and during the period of attachment the vehicle did not remain in his possession:

Provided that the period of such surrender or non-use shall not be less than seven days for stage carriages and less than one month for other than stage carriages:

Provided further that where a motor vehicle, other than those which has paid one time tax under clause (b) or clause (e) of sub-section (1) of section 4 or lump sum tax under section 4-C, is found plying after the surrender of the certificate of registration, the tax on such vehicle shall be payable forthwith for the entire period for which such registration was surrendered alongwith a penalty equal to five times the amount of tax but no such tax or penalty shall be charged from empty vehicle going for repair or for test purposes.

4-B. Special Road Tax.- In addition to the tax levied under section 4 and subject to the rules as may be made by the State Government in this behalf, there shall be levied and paid to the State Government a special Road Tax on all transport vehicles except those transport vehicles which have paid lump sum tax payable under section 4-C at the rates as may be specified by notification in the Official Gazette, by the State Government which shall not exceed Rs 2,000/- per day in respect of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 250/- per thousand Kg. of load carrying capacity or part thereof for thirty days in respect of goods vehicles of other States or for vehicle plying on temporary permits of this State, and not exceeding 5% of the cost of the chassis/vehicle per month in respect of other vehicles.

Explanation.- The cost of the chassis/vehicle for the purposes of computation of tax shall include purchase price and such other elements as may be prescribed by the State Government:

Provided further that where a motor vehicle other than those which has paid one time tax under section 4-C is found plying after the surrender of the certificate of registration, the special road tax on such vehicle shall be payable forthwith for the entire period for which such certificate of registration was surrendered, alongwith a penalty equal to five times the amount of Special Road Tax but no such tax or penalty shall be charged from empty vehicle going for repair or test purposes.

4-C. Imposition of Lump sum tax.- Notwithstanding anything contained in section 4 and section 4-B and subject to the rules as may be made by the State Government there shall be levied and paid to the State Government a lump sum tax on all transport vehicles at the rates as may be specified by the notification in the Official Gazette by the State Government which shall not exceed 50% of the cost of vehicle/chassis:

Provided that the owner or person having possession or control of transport vehicle shall have option either to pay tax levied under clause (a) or clause (e) of sub-section (1) of section 4 and section 4-B or lump sum tax under section 4-C:

Provided further that the State government may by notification in the Official Gazette require the owners or the persons having possession of such class of transport vehicles registered on or after 1-4-2007 as may be specified in the notification to pay lump sum tax under section 4-C instead of tax payable under clause (a) or clause (e) of sub-section (1) of section 4 and section 4-B.

4-D. Levy of Green Tax.- (1) There shall be levied and collected a cess called “green tax”, in addition to the tax levied under sections 4, 4-B and 4-C of the Act, on such vehicles suitable for use on road as specified in column (2), at such time as specified in column (3), of the table below at such rates, not exceeding the maximum rates specified in column (4) of the table, as may be fixed by the State Government by notification in the Official Gazette, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution.

Table

XX	XX	XX	XX
(2)	XX	XX	XX

4-E. Levy of Surcharge.- (1) Notwithstanding anything contained in sections 4, 4-B and 4-C of the Act, the tax imposed by the said sections shall with effect from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2011 (Act No. 15 of 2011) be increased by a surcharge at such rates, not exceeding 20 % of the said tax, as may be specified by the State Government by the notification in Official Gazette.

(2)	XX	XX	XX
-----	----	----	----

5. Payment of Tax.- (1) Save as otherwise provided by or under this Act and subject to the provisions of sub-section (2), the tax leviable under section 4, section 4-B and section 4-C shall be paid by every owner or by the person having possession or control of a motor vehicle in advance in the manner prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, if satisfied that there are sufficient reasons for doing so, by notification in the Official Gazette, extend whether prospectively or retrospectively the time limit for payment of tax in case of particular classes of vehicles or persons liable to pay tax under this Act:

Provided further that the lump sum tax payable under section 4-C may be paid in full or in six equal instalments within a period of one year in such manner as may be prescribed by the State Government.

(2) Where the tax on any motor vehicle becomes payable otherwise than as one time tax or lump sum tax, for the first time after the commencement of a financial year, the tax payable shall be one twelfth of the annual rate for each calendar month or part thereof where annual rate is prescribed:

Provided that where the tax under section 4-B on stage carriage other than those plying exclusively on city routes becomes payable for the first time after the commencement of any month, the tax payable shall be for the remaining period of that month on pro rata basis:

Provided further that where the tax under section 4-B on contract carriage becomes payable for the first time after the commencement of any month, the tax payable shall be for the remaining period of the month on pro rata basis.

(3) The tax payable under clause (b) or (e) of sub-section (1) of section 4 or full tax or first instalment of tax under section 4-C shall be payable-

(a) where the motor vehicle is purchased or brought into the State for use or is kept for use on or after the coming into force of the provisions of Chapter V of the Rajasthan Finance Act, 2005 (Act No. 15 of 2005), within thirty days of the date of such purchase or of being so brought or on the date of registration or assignment of such vehicle in the State, whichever is earlier; or

(b) where the motor vehicle has been used or kept for use in the State before the coming into force of the provisions of Chapter V of the Rajasthan Finance Act, 2005 (Act No. 15 of 2005) within sixty days of such coming into force.

(4) Where a motor vehicle is found plying after the surrender of the certificate of registration, the tax levied under section 4 and section 4-B on such vehicle shall be payable forthwith by the owner or person having possession or control of the motor vehicle, for the entire period for which such certificate was surrendered, along with a penalty equal to five times the amount of tax but no such tax or penalty shall be charged from empty vehicle going for repairs or for test purposes.

XX

XX

XX

XX

7. Refund of tax.- (1) When any person who has paid the tax other than one-time tax under clause (b) or (e) of sub-section (1) of section 4 or lump sum tax under section 4-C or instalment of tax, proves to the satisfaction of the

Taxation Officer that the motor vehicle in respect of which such tax or instalment has been paid, has not been used for a continuous period of not less than one month since the tax or instalment was last paid, he shall be entitled to the refund of an amount equal to 1/12th of the annual rate of the tax paid in respect of such vehicle for each complete month of the period for which such tax or instalment has been paid.

(2) When any person who has paid one-time tax under clause (b) or clause (e) of sub-section (1) of section 4 or lump sum tax under section 4-C proves to the satisfaction of the taxation officer that the motor vehicle, in respect of which such tax has been paid, has been taken out of the State or has completely been destroyed or has been converted into a vehicle liable to pay less amount of tax shall be entitled to the refund of such tax on pro rata basis in the prescribed manner.

(3) The Taxation Officer may refund or adjust in the prescribed manner any amount paid in excess of the tax due.

XX

XX

XX

XX

10. Grant of receipt and token or tax certificate.- (1) The Taxation Officer shall grant and deliver to every person who pays to him the tax,-

- (a) in respect of any motor vehicle covered under clause (b) of sub-section (1) of section 4, a receipt specifying the particulars of tax paid and also a tax certificate in such form and containing such particulars as may be prescribed; or
- (b) in respect of motor vehicle other than that covered by clause (a) above, a receipt as aforesaid and a token in such form and containing such particulars as may be prescribed:

Provided that no token shall be issued in respect of a transport vehicle if the special road tax payable under section 4-B and the outstanding dues and further demand created, if any, under the Rajasthan Passengers and Goods Taxation Act, 1959 (Rajasthan Act 18 of 1959), as it stood before the Rajasthan Passengers and Goods Taxation (Repealing) Act, 1982 have not been paid.

(2) No motor vehicle liable to tax under this Act shall be used or kept for use in Rajasthan unless the owner or any person having possession or control thereof has obtained,-

- (a) in case of a vehicle covered under clause (b) and clause (e) of sub-section (1) of section 4, a tax certificate which shall always be kept in such vehicle, or

(b) in case of a vehicle other than that covered under clause (a) above, a valid token which shall always be exhibited on such vehicle in the prescribed manner.

10-A. Grant of special token.- Any owner of a motor vehicle who has paid the motor vehicle tax and special road tax in advance may apply to the Taxation Officer for grant of special token on payment of prescribed fee and the Taxation Officer shall issue the special token in such manner, as may be prescribed.

10-B. Computerisation.- The work of grant of receipt, tax certificate, token, special token, etc., under this Act may be computerized in such manner, as may be prescribed. Such work may be entrusted to any agency and the cost incurred may be realised from the owner of the vehicle in such manner, as may be prescribed.

11. Offences.- (1) Whoever,-

- (a) as a registered owner or otherwise, has the possession or control of any motor vehicle used or kept for use in the State without having paid the amount of the tax, or additional tax or special road tax, due in accordance with the provisions of this Act in respect of such vehicle; or
- (b) delivers a declaration or additional declaration wherein the particulars required by or under this Act, to be therein set forth, are not fully and truly stated; or
- (c) obstructs any officer in the exercise of the powers conferred by section 18 or fails to stop the motor vehicle when required so to do by such officer under section 17;

shall on conviction, be punishable, with fine which shall not be less than twice the annual tax payable in respect of such vehicle but which may extend to five times of such annual tax.

(2) XX XX XX
XX XX XX XX

22. Power of State Government to make rules.- (1) XX XX

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules for all or any of the following purposes, that is to say-

- (a) to (aa) XX XX XX

